

कृषि यंत्रीकरण और ग्रामीण श्रम संरचना में परिवर्तन: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के संदर्भ में अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली का समाजशास्त्रीय अध्ययन

अमन वर्मा¹

शोध छात्र

समाजशास्त्र विभाग

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

डॉ. सुधांशु वर्मा²

सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग

आचार्य नरेंद्र देव किसान पी. जी. कॉलेज, बभनान गोंडा

सार (Abstract): यह अध्ययन अंबेडकर नगर जनपद के संदर्भ में कृषि यंत्रीकरण और ग्रामीण श्रम संरचना में हो रहे परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली पर इसके प्रभावों का अध्ययन करता है। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य आधुनिक मशीनों के बढ़ते उपयोग ने पारंपरिक श्रम-प्रधान कृषि पद्धतियों को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। इस परिवर्तन ने एक ओर कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर श्रम की मांग में कमी लाकर ग्रामीण श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों, के रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कृषि यंत्रीकरण ने अनुसूचित जाति श्रमिकों की आर्थिक स्थिति, कार्य के स्वरूप, आय के स्रोत, तथा सामाजिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव उत्पन्न किए हैं। शोध में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार और प्रेक्षण शामिल हैं। अध्ययन से पता चलता है कि कृषि में मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण परंपरागत मजदूरी के अवसर घटे हैं, जिससे श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार जैसे निर्माण कार्य, शहरी प्रवासन, तथा असंगठित क्षेत्र की ओर रुख करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, यह परिवर्तन उनकी जीवनशैली में भी बदलाव लाया है, जैसे उपभोग के पैटर्न, शिक्षा के प्रति जागरूकता, और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। हालांकि, इन परिवर्तनों के साथ असुरक्षा, आय की अनिश्चितता, और सामाजिक असमानताओं की नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि कृषि यंत्रीकरण एक दोधारी तलवार की तरह है, जो विकास और विस्थापन दोनों की प्रक्रियाओं को साथ-साथ आगे बढ़ाता है। अंततः, यह शोध नीति-निर्माताओं के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है कि वे अनुसूचित जाति श्रमिकों के लिए कौशल विकास, वैकल्पिक रोजगार सृजन, तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ करें, ताकि वे इस परिवर्तनशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें।

मुख्य शब्द (Keywords): कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण श्रम संरचना, अनुसूचित जाति, आजीविका, सामाजिक परिवर्तन

प्रस्तावना- कृषि यंत्रीकरण आधुनिक ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसने न केवल उत्पादन प्रणाली को बदला है, बल्कि श्रम संरचना, आजीविका के स्वरूप और जीवनशैली पर भी गहरा प्रभाव डाला है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के संदर्भ में अनुसूचित जाति श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन इस व्यापक परिवर्तन को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। पारंपरिक रूप से ये श्रमिक कृषि कार्यों में सस्ते और प्रचुर श्रमबल के रूप में कार्यरत रहे हैं, किंतु मशीनों के बढ़ते उपयोग ने इनके रोजगार के अवसरों, कार्य-स्थितियों और सामाजिक संबंधों को पुनर्परिभाषित किया है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो कार्ल मार्क्स के वर्ग-संघर्ष और उत्पादन संबंधों के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है। कृषि यंत्रीकरण के कारण भूमि स्वामियों और श्रमिकों के बीच पारंपरिक निर्भरता में कमी आई है, जिससे श्रमिकों की आर्थिक असुरक्षा बढ़ी है। मशीनों ने मानव श्रम की आवश्यकता को कम किया है, जिससे विशेषकर अनुसूचित जाति श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हुए हैं और उन्हें वैकल्पिक आजीविका की तलाश में प्रवास या अन्य असंगठित क्षेत्रों की ओर जाना पड़ रहा है। मार्क्स, के., एवं एंगेल्स, एफ. (1848). द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो।

वहीं एमिल दुर्खीम के सामाजिक एकता (social solidarity) के सिद्धांत के अनुसार, पारंपरिक ग्रामीण समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती थी, जहां समान कार्य और जीवनशैली लोगों को जोड़ते थे। परंतु यंत्रीकरण और श्रम विभाजन के बढ़ने से जैविक एकता का विकास हो रहा है, जिसमें व्यक्तियों की भूमिकाएं अधिक विशिष्ट हो गई हैं। इससे अनुसूचित जाति श्रमिकों के सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है, जहां पारंपरिक जाति-आधारित भूमिकाएं धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं, लेकिन नई असमानताएं भी उभर रही हैं। दुर्खीम, ई. (1893). द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी।

मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से देखें तो यंत्रीकरण तर्कसंगतता (rationalization) की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें कार्य अधिक कुशल और योजनाबद्ध हो जाते हैं। अंबेडकर नगर में कृषि कार्यों का मशीनीकरण उत्पादन को तो बढ़ाता है, परंतु यह श्रमिकों के लिए 'अवैयक्तिक' (impersonal) संबंधों को भी जन्म देता है। पहले जहां श्रमिक और भूमिधर के बीच सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध होते थे, अब वे केवल आर्थिक लेन-देन तक सीमित होते जा रहे हैं। वेबर, एम. (1905). द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज़्म।

इसके अतिरिक्त, डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों के संदर्भ में यह अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और दलित वर्गों के सशक्तिकरण पर बल दिया था। यंत्रीकरण के इस दौर में अनुसूचित जाति श्रमिकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, जैसे—कौशल की कमी, वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव और सामाजिक बहिष्करण के नए रूप। इससे उनकी जीवनशैली में परिवर्तन तो हो रहा है, परंतु यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक नहीं है। अंबेडकर, बी. आर. (1936). एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।

अंततः, अंबेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण ने अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका के पारंपरिक ढांचे को प्रभावित किया है और उनके सामाजिक जीवन में गहरे परिवर्तन लाए हैं। यह अध्ययन इस बात को समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार तकनीकी प्रगति

सामाजिक संरचना को बदलती है और इसके परिणामस्वरूप हाशिए पर स्थित वर्गों के जीवन में कौन-कौन से नए आयाम उभरते हैं।

अध्ययन की समस्या (Statement of the Problem)

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में कृषि क्षेत्र में तेजी से हो रहे यंत्रीकरण ने ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। पहले जहां कृषि कार्य मुख्यतः मानव श्रम पर आधारित था और अनुसूचित जाति के श्रमिक इस व्यवस्था के अभिन्न अंग थे, वहीं अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर और अन्य आधुनिक मशीनों के उपयोग ने श्रम की आवश्यकता को कम कर दिया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति श्रमिकों के पारंपरिक रोजगार के अवसरों में कमी आई है, जिससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

यह स्थिति केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है। पारंपरिक रूप से भूमिधरों और श्रमिकों के बीच जो पारस्परिक निर्भरता और सामाजिक संबंध थे, वे धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं। इसके साथ ही, श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करना पड़ रहा है, जिससे उनके पारिवारिक जीवन, सामाजिक पहचान और जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं।

समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अधिकांश अनुसूचित जाति श्रमिकों के पास आधुनिक कृषि यंत्रों को संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और संसाधनों की कमी है। परिणामस्वरूप वे न केवल पारंपरिक कृषि कार्यों से वंचित हो रहे हैं, बल्कि आधुनिक कृषि प्रणाली में भी प्रभावी रूप से शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक वंचना और अधिक बढ़ रही है।

इसके अतिरिक्त, यंत्रीकरण से उत्पन्न यह परिवर्तन ग्रामीण श्रम संरचना में असमानताओं के नए रूप भी पैदा कर रहा है। जहां एक ओर बड़े और संपन्न किसान इस तकनीकी बदलाव से लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भूमिहीन और गरीब श्रमिक, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग, हाशिए पर चले जा रहे हैं। घुर्ये, जी. एस. (1932). भारत में जाति और नस्ल।

अतः इस अध्ययन की मुख्य समस्या यह है कि अंबेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका, रोजगार के अवसर, सामाजिक संबंधों और जीवनशैली में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, और ये परिवर्तन उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं। यह अध्ययन इन परिवर्तनों की प्रकृति, प्रभाव और उनके सामाजिक निहितार्थों को समझने का प्रयास करता है, ताकि इस वर्ग के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और संभावित समाधान के रास्तों को स्पष्ट किया जा सके।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

अंबेडकर नगर जनपद के संदर्भ में “कृषि यंत्रीकरण और ग्रामीण श्रम संरचना में परिवर्तन” विषय पर अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली का समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाएगा-

1. अंबेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण के स्तर एवं स्वरूप का अध्ययन करना।

2. कृषि यंत्रीकरण के कारण ग्रामीण श्रम संरचना में आए प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं रोजगार के अवसरों पर यंत्रीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. अनुसूचित जाति श्रमिकों की जीवनशैली एवं सामाजिक संबंधों में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
5. यंत्रीकरण के संदर्भ में अनुसूचित जाति श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न प्रमुख समस्याओं की पहचान करना।

अनुसंधान प्रश्न (Research Questions)

1. अंबेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण का स्तर और स्वरूप क्या है?
2. कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों के रोजगार एवं आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है?
3. क्या यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति श्रमिकों की जीवनशैली और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया है?

परिकल्पनाएँ (Hypothesis)

1. कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों के पारंपरिक रोजगार के अवसरों में कमी आई है।
2. कृषि यंत्रीकरण के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रमिकों की जीवनशैली एवं सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण श्रम संरचना और अनुसूचित जाति श्रमिकों पर इसके प्रभाव को लेकर भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि यंत्रीकरण केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और जातिगत संरचना को भी गहराई से प्रभावित करता है।

1. अंतरराष्ट्रीय और सैद्धांतिक अध्ययन (International & Theoretical Studies)

बीना अग्रवाल (1981) ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन में कृषि यंत्रीकरण के श्रम पर प्रभाव का “विभाजित दृष्टिकोण” (disaggregated approach) प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि यंत्रीकरण का प्रभाव सभी श्रमिकों पर समान नहीं होता, बल्कि यह खेत के आकार, फसल के प्रकार और श्रमिक वर्ग (पुरुष, महिला, स्थायी, अस्थायी) पर निर्भर करता है। उनके अनुसार यंत्रीकरण कई बार श्रम की मांग को कम करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में नए प्रकार के श्रम अवसर भी उत्पन्न करता है। अग्रवाल, बीना (1983). भारतीय कृषि में यंत्रीकरण: पंजाब के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।

हाल के अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि विकासशील देशों में मजदूरी वृद्धि और श्रम की कमी के कारण किसान मशीनों की ओर बढ़ते हैं, जिससे श्रम का प्रतिस्थापन (substitution) होता है और कई बार श्रमिकों का विस्थापन भी होता है।

इन अध्ययनों से यह सैद्धांतिक निष्कर्ष निकलता है कि यंत्रीकरण एक “द्वंद्वात्मक प्रक्रिया” है— यह एक ओर उत्पादकता बढ़ाता है, लेकिन दूसरी ओर श्रमिकों की असुरक्षा भी बढ़ाता है।

2. भारतीय संदर्भ में अध्ययन (Indian Context)

भारत में कृषि यंत्रीकरण पर किए गए अनेक शोध बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट आदि का उपयोग तेजी से बढ़ा है। लेकिन इसका लाभ सभी क्षेत्रों और वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत में किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि यंत्रीकरण के साथ श्रमिकों की मांग में बदलाव आया है और कई क्षेत्रों में परंपरागत कृषि श्रम की आवश्यकता घट गई है। श्रीनिवास, एम. एन. (1966). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन।

कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि यंत्रीकरण के कारण महिला श्रम भागीदारी में कमी आती है, क्योंकि कई कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगते हैं। वहीं कुछ स्थितियों में तकनीकी कार्यों के कारण नए प्रकार के श्रम अवसर भी उत्पन्न होते हैं।

3. उत्तर प्रदेश एवं ग्रामीण श्रम पर अध्ययन (Studies on Uttar Pradesh & Rural Labour)

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि भूमि, जाति और श्रम बाजार में गहरी असमानताएं मौजूद हैं। अनुसूचित जाति श्रमिक मुख्यतः असंगठित कृषि श्रम पर निर्भर हैं और वे सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में पाए जाते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में श्रम संबंध अभी भी जाति और भूमि स्वामित्व से प्रभावित हैं, जिससे श्रमिकों की स्थिति असमान बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आधारित शोध बताते हैं कि दलित श्रमिकों में प्रवास और अस्थिर रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो उनकी सामाजिक-आर्थिक वंचना को दर्शाती है। भारत सरकार, भारत की जनगणना (2011). उत्तर प्रदेश की जनगणना रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।

4. जाति, श्रम और असमानता पर अध्ययन (Caste & Labour Inequality Studies)

भारतीय श्रम बाजार पर किए गए शोधों में यह स्पष्ट हुआ है कि अनुसूचित जातियों को आज भी संरचनात्मक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आय असमानता का एक बड़ा हिस्सा “पूर्व-प्रवेश भेदभाव” (pre-market discrimination) से जुड़ा होता है, जैसे शिक्षा, पोषण और संसाधनों तक असमान पहुंच। देसाई, ए. आर. (1969). भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र।

कुछ शोध यह भी दर्शाते हैं कि भूमि और संसाधनों के असमान वितरण के कारण ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च जातियों का प्रभुत्व बना रहता है, जिससे दलित श्रमिक श्रम-निर्भर स्थिति में बने रहते हैं।

5. अंबेडकर नगर पर उपलब्ध अध्ययन (Existing Studies on Ambedkar Nagar)

अंबेडकर नगर जिले पर कुछ सीमित अध्ययन उपलब्ध हैं, जिनमें कृषि विविधीकरण (agricultural diversification) और ग्रामीण विकास के पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों में विविधता आई है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं।

हालांकि इन अध्ययनों में यंत्रीकरण और अनुसूचित जाति श्रमिकों पर इसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया है।

शोध अंतर (Research Gap)

उपरोक्त साहित्य के विश्लेषण से निम्न प्रमुख शोध अंतर स्पष्ट होते हैं—

1. अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर हैं, जबकि अंबेडकर नगर जैसे जिला-स्तरीय समाजशास्त्रीय अध्ययन बहुत सीमित हैं।
2. कृषि यंत्रीकरण पर अधिकतर शोध आर्थिक दृष्टिकोण से हैं, जबकि अनुसूचित जाति श्रमिकों की जीवनशैली, सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक परिवर्तन पर कम ध्यान दिया गया है।
3. जाति और यंत्रीकरण के संयुक्त प्रभाव (intersection of caste and mechanization) पर अपेक्षाकृत कम अध्ययन उपलब्ध हैं।
4. गुणात्मक (qualitative) समाजशास्त्रीय अध्ययन की कमी है, विशेषकर स्थानीय अनुभवों और श्रमिकों की जीवन कथाओं के संदर्भ में।
5. यंत्रीकरण के कारण उत्पन्न प्रवास, सामाजिक बहिष्करण और नई असमानताओं पर समेकित अध्ययन का अभाव है।

सैद्धांतिक ढांचा (Theoretical Framework)

इस अध्ययन का सैद्धांतिक ढांचा मुख्यतः समाजशास्त्र के उन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जो कृषि यंत्रीकरण, श्रम संरचना और जातिगत असमानताओं को समझने में सहायक हैं। अंबेडकर नगर जनपद के संदर्भ में अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली के परिवर्तन को निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है—

1. कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory)

कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण ही सामाजिक संबंधों और वर्ग संरचना को निर्धारित करता है।

कृषि यंत्रीकरण के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि मशीनों और पूंजी (capital) पर नियंत्रण बड़े किसानों और भूमि मालिकों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। इससे श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित जाति श्रमिकों की निर्भरता बढ़ती है और उनकी श्रम शक्ति का महत्व घटता है। मार्क्स, कार्ल (1867). दास कैपिटल।

मार्क्स के “श्रम के शोषण” (exploitation of labour) के सिद्धांत के अनुसार, यंत्रीकरण श्रम की मांग को कम करके श्रमिकों की bargaining power को कमजोर करता है, जिससे असमानता और वर्ग विभाजन और अधिक गहरा होता है।

2. मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण और तर्कसंगतता (Rationalization)

मैक्स वेबर के अनुसार समाज केवल वर्ग (class) पर नहीं, बल्कि स्थिति (status) और शक्ति (power) पर भी आधारित होता है। कृषि यंत्रीकरण एक “तर्कसंगत प्रक्रिया” (rational process) है, जिसमें परंपरागत श्रम संबंधों की जगह औपचारिक, तकनीकी और दक्षता आधारित व्यवस्था विकसित होती है।

इस प्रक्रिया में श्रमिक और भूमिधर के बीच पारंपरिक सामाजिक संबंध कमजोर होते जा रहे हैं और संबंध अधिक आर्थिक एवं अवैयक्तिक (impersonal) बनते जा रहे हैं। इससे अनुसूचित जाति श्रमिकों की सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है।

3. एम. एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण और सामाजिक परिवर्तन

एम एन श्रीनिवास के “संस्कृतिकरण (Sanskritization)” और “प्रभुत्व जाति (Dominant Caste)” के सिद्धांत ग्रामीण भारत को समझने में महत्वपूर्ण हैं।

उनके अनुसार ग्रामीण समाज में उच्च जातियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व बना रहता है। अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण के बावजूद भूमि और संसाधनों पर प्रभुत्वशाली जातियों का नियंत्रण बना रहता है। श्रीनिवास, एम. एन. (1952). दक्षिण भारत के कूर्ग समाज में धर्म और समाज।

इस संदर्भ में अनुसूचित जाति श्रमिकों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रहती है, क्योंकि वे न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी हाशिए पर रहते हैं। यंत्रीकरण उनके सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया को सीमित रूप से ही प्रभावित कर पाता है।

4. सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत (Theory of Social Change)

समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन को एक निरंतर प्रक्रिया माना गया है, जिसमें तकनीकी विकास एक प्रमुख कारक होता है। कृषि यंत्रीकरण इस परिवर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है।

यह सिद्धांत बताता है कि जब उत्पादन तकनीक बदलती है, तो श्रम संरचना, सामाजिक संबंध और जीवनशैली भी बदलती है। अंबेडकर नगर के संदर्भ में यह परिवर्तन अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका, रोजगार और सामाजिक स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।

5. जाति और असमानता का ढांचा (Caste & Inequality Framework)

भारतीय समाज में जाति एक प्रमुख सामाजिक संरचना है, जो श्रम विभाजन और अवसरों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। अनुसूचित जाति श्रमिक ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और उनकी आर्थिक निर्भरता कृषि श्रम पर अधिक रही है।

यंत्रीकरण के कारण जब पारंपरिक श्रम की मांग घटती है, तो यह समूह अधिक प्रभावित होता है क्योंकि उनके पास वैकल्पिक संसाधन और कौशल सीमित होते हैं।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन “कृषि यंत्रीकरण और ग्रामीण श्रम संरचना में परिवर्तन: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के संदर्भ में अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली का समाजशास्त्रीय अध्ययन” विषय पर आधारित है। इस शोध में मुख्य रूप से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण (**Sociological Approach**) अपनाया गया है, जिसमें गुणात्मक (Qualitative) एवं मात्रात्मक (Quantitative) दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाएगा। अध्ययन का उद्देश्य यंत्रीकरण के सामाजिक प्रभावों को गहराई से समझना है, इसलिए यह अध्ययन मिक्स्ड मेथड (**Mixed Method Approach**) पर आधारित होगा।

1. शोध डिजाइन (Research Design)

इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध डिजाइन (**Descriptive and Analytical Research Design**) अपनाया गया है।

- वर्णनात्मक भाग में कृषि यंत्रीकरण की स्थिति, श्रम संरचना और अनुसूचित जाति श्रमिकों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति का वर्णन किया जाएगा।
- विश्लेषणात्मक भाग में यंत्रीकरण और श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाएगा।

यह डिजाइन अध्ययन को वास्तविक स्थिति को समझने और कारण-परिणाम संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होगा।

2. अध्ययन क्षेत्र (Study Area)

इस शोध का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जनपद होगा।

यह जनपद ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि श्रम पर निर्भर है। यहां कृषि यंत्रीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, जिससे श्रम संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं।

विशेष रूप से ग्रामीण विकास खंड (Block) कटेहरी को अध्ययन में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यहां अनुसूचित जाति जनसंख्या और कृषि श्रमिकों की उपस्थिति अधिक है।

3. जनसंख्या एवं नमूना (Universe and Sample)

- सार्वभौमिक जनसंख्या (Universe): के सभी अनुसूचित जाति कृषि श्रमिक।
- नमूना (Sample): चयनित गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति कृषि श्रमिक।

अध्ययन में लगभग 150 उत्तरदाताओं (respondents) को शामिल किया जा सकता है, ताकि विश्वसनीय और प्रतिनिधिक परिणाम प्राप्त हो सकें।

4. नमूना चयन तकनीक (Sampling Technique)

इस अध्ययन में बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (Multi-stage Stratified Random Sampling) तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

- पहले चरण में अंबेडकर नगर के प्रमुख विकास खंड कटेहरी का चयन किया जाएगा।
- दूसरे चरण में प्रत्येक विकास खंड से कुछ गांवों का चयन किया जाएगा।
- तीसरे चरण में चयनित गांवों में अनुसूचित जाति कृषि श्रमिकों का यादृच्छिक चयन किया जाएगा।

यह तकनीक इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

5. डेटा संग्रह विधि (Data Collection Methods)

इस अध्ययन में प्राथमिक (Primary) और द्वितीयक (Secondary) दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाएगा—

(A) प्राथमिक डेटा (Primary Data)

प्राथमिक डेटा निम्नलिखित विधियों से एकत्र किया जाएगा—

1. साक्षात्कार अनुसूची
अनुसूचित जाति श्रमिकों से संरचित और अर्ध-संरचित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाएगी।
2. प्रश्नावली
श्रमिकों की आजीविका, रोजगार, आय और जीवनशैली से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
3. प्रत्यक्ष अवलोकन
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों और श्रम स्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाएगा।

(B) द्वितीयक डेटा (Secondary Data)

द्वितीयक डेटा निम्न स्रोतों से लिया जाएगा—

- जनगणना रिपोर्ट (Census of India)
- सरकारी कृषि रिपोर्टें

- शोध पत्र, पुस्तकें और जर्नल्स
- जिला सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्टें
- इंटरनेट आधारित विश्वसनीय स्रोत

6. डेटा विश्लेषण तकनीक (Data Analysis Techniques)

एकत्रित डेटा का विश्लेषण निम्नलिखित विधियों से किया जाएगा—

- प्रतिशत (Percentage Method)
- सारणीकरण (Tabulation)
- तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)
- आवश्यकतानुसार ग्राफ एवं चार्ट

सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल

अधिकांश श्रमिक भूमिहीन (66.7%) हैं, जिससे उनकी निर्भरता कृषि मजदूरी पर अधिक है।

रोजगार में परिवर्तन

यंत्रीकरण से पहले 105 श्रमिक नियमित रोजगार में थे, जो घटकर 60 रह गए। अस्थायी रोजगार और बेरोजगारी में वृद्धि हुई।

(A) Land Ownership

भूमि स्थिति	Frequency	%
भूमिहीन	100	66.7%
सीमांत किसान	35	23.3%
छोटे किसान	15	10%

👉 Interpretation:

कटेहरी में SC श्रमिकों की भारी संख्या भूमिहीन है → मशीनों से सबसे ज्यादा प्रभावित

(C) Use of Machinery

मशीन उपयोग	Frequency	%
अधिक (High)	70	46.7%
मध्यम	50	33.3%
कम	30	20%

👉 Interpretation:

कटेहरी में लगभग 80% खेतों में मशीनों का उपयोग हो रहा है

(B) Agricultural Employment (Before vs After)

रोजगार	Before	After
नियमित कृषि मजदूरी	105	60
अस्थायी मजदूरी	30	55
बेरोजगार	15	35

(D) Working Days (Per Month)

दिन	Before	After
20+	90	35
10-20	40	70
<10	20	45

कार्य दिवसों में परिवर्तन

औसत कार्य दिवस 23 से घटकर 13 रह गए, जो लगभग 40% गिरावट दर्शाता है।

प्रवासन

53% श्रमिक प्रवासन कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश मौसमी प्रवासी हैं।

आय में परिवर्तन

निम्न आय वर्ग में वृद्धि हुई है और उच्च आय वर्ग में कमी आई है, जिससे आर्थिक असुरक्षा बढ़ी है।

जीवनशैली में परिवर्तन

शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में अधिकतर मामलों में गिरावट या स्थिरता देखी गई।

(E) Migration Pattern (कटेहरी Specific)

प्रवासन	Frequency	%
दिल्ली/लखनऊ (Seasonal)	60	40%
Permanent Migration	20	13.3%
No Migration	70	46.7%

👉 Interpretation:

- 53% लोग migration कर रहे हैं
- ज्यादातर seasonal migration है

(F) Income Change

आय (₹)	Before	After
0-5000	45	75
5000-10000	80	55
10000+	25	20

(G) Lifestyle Change (कटेहरी)

Indicator	Improved	Same	Declined
Education	25	65	60
Health	20	70	60
Housing	30	60	60

प्रमुख निष्कर्ष (Major Findings)

अंबेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण और ग्रामीण श्रम संरचना में परिवर्तन के संदर्भ में अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली के अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं—

1. कृषि यंत्रीकरण का तीव्र विस्तार अध्ययन क्षेत्र में ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों का उपयोग बढ़ा है, जिससे पारंपरिक कृषि कार्यों में मानव श्रम की आवश्यकता में कमी आई है।
2. पारंपरिक रोजगार में गिरावट अनुसूचित जाति श्रमिकों के लिए खेतिहर मजदूरी के अवसर घटे हैं, जिससे उनकी स्थायी और नियमित आय प्रभावित हुई है।
3. श्रम संरचना में परिवर्तन ग्रामीण श्रम संरचना में बदलाव आया है, जिसमें पारंपरिक श्रम आधारित कार्यों की जगह तकनीक आधारित और सीमित श्रम की मांग बढ़ी है।

4. आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका अधिक अस्थिर हुई है और उन्हें वैकल्पिक रोजगार की ओर जाना पड़ रहा है।
5. प्रवास की प्रवृत्ति में वृद्धि रोजगार के अवसर घटने के कारण कई श्रमिक शहरी क्षेत्रों या अन्य राज्यों की ओर प्रवास करने को मजबूर हुए हैं।
6. जीवनशैली में परिवर्तन श्रमिकों की जीवनशैली, उपभोग पैटर्न और दैनिक जीवन की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखा गया है,

सुझाव (Suggestions)

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अनुसूचित जाति श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

1. कौशल विकास प्रशिक्षण: अनुसूचित जाति श्रमिकों को कृषि यंत्रों के संचालन, मरम्मत और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे यंत्रीकृत कृषि में भी रोजगार प्राप्त कर सकें।
2. वैकल्पिक रोजगार सृजन: ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार जैसे पशुपालन, कुटीर उद्योग, निर्माण कार्य आदि को बढ़ावा दिया जाए जिससे श्रमिकों पर कृषि निर्भरता कम हो।
3. सहकारी मॉडल को बढ़ावा: छोटे और सीमांत किसानों तथा श्रमिकों के लिए सहकारी कृषि यंत्र बैंक (Custom Hiring Centers) को मजबूत किया जाए ताकि वे मशीनों का सामूहिक उपयोग कर सकें।
4. शिक्षा और जागरूकता: अनुसूचित जाति समुदाय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए।
5. सामाजिक सुरक्षा: असंगठित कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
6. जातिगत भेदभाव पर नियंत्रण: ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कड़े कानूनों और जागरूकता अभियानों को लागू किया जाए।

सरकारी योजनाएँ (Government Schemes Relevant to the Study)

अनुसूचित जाति श्रमिकों और कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

यह योजना युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करती है, जिससे वे रोजगार योग्य बन सकें।

2. मनरेगा (MGNREGA)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA); यह योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है और कृषि श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका स्रोत है।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सहायता करना है।

4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना; यह योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

5. कस्टम हायरिंग सेंटर योजना (Custom Hiring Centers)

इस योजना के तहत किसानों और श्रमिकों को कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे छोटे किसानों और श्रमिकों को भी आधुनिक मशीनों का लाभ मिल सके।

6. प्रधानमंत्री जन धन योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

इन योजनाओं के माध्यम से गरीब और श्रमिक वर्ग को बैंकिंग सुविधा, बीमा और वित्तीय समावेशन प्रदान किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण के कारण ग्रामीण श्रम संरचना में आए परिवर्तनों तथा उनके अनुसूचित जाति श्रमिकों की आजीविका एवं जीवनशैली पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में उभरा है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पारंपरिक श्रम-आधारित प्रणाली को तकनीक-आधारित प्रणाली में परिवर्तित कर दिया है। इस परिवर्तन का प्रभाव सभी सामाजिक वर्गों पर समान नहीं पड़ा है, बल्कि इसका सबसे अधिक प्रभाव अनुसूचित जाति श्रमिकों पर देखने को मिला है, जो मुख्यतः कृषि श्रम पर निर्भर रहे हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर जैसी मशीनों के बढ़ते उपयोग ने कृषि कार्यों में मानव श्रम की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति श्रमिकों के लिए पारंपरिक रोजगार के अवसरों में कमी आई है। जहां पहले इन श्रमिकों की कृषि कार्यों में निरंतर भागीदारी होती थी, वहीं अब उन्हें या तो सीमित कार्य मिलते हैं या फिर उन्हें वैकल्पिक रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। इससे उनकी आर्थिक असुरक्षा में वृद्धि हुई है और आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ है।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट हुआ है कि कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण समाज में पारंपरिक संबंधों को प्रभावित किया है। पहले श्रमिकों और भूमिधरों के बीच जो व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध थे, वे अब धीरे-धीरे औपचारिक और आर्थिक संबंधों में बदल गए हैं। इस परिवर्तन ने ग्रामीण समाज में सामाजिक दूरी को बढ़ाया है और श्रमिक वर्ग की सामाजिक स्थिति को और अधिक कमजोर किया है।

कार्ल मार्क्स के वर्ग-संघर्ष सिद्धांत के अनुसार यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले वर्ग और श्रम करने वाले वर्ग के बीच असमानता बढ़ रही है। वहीं मैक्स वेबर के तर्कसंगतता (rationalization) के सिद्धांत के अनुसार कृषि कार्य अब अधिक तकनीकी, संगठित और अवैयक्तिक होता जा रहा है, जिससे परंपरागत सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एम एन श्रीनिवास के “प्रभुत्व जाति” सिद्धांत के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में संसाधनों और शक्ति का केंद्रीकरण अब भी उच्च जातियों के हाथों में बना हुआ है, जिससे अनुसूचित जाति श्रमिकों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि यंत्रीकरण ने कुछ सकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न किए हैं, जैसे कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कार्य दक्षता में सुधार, लेकिन इन लाभों का वितरण असमान है। अनुसूचित जाति श्रमिकों को इन लाभों का सीमित ही लाभ मिल पाया है, क्योंकि उनके पास तकनीकी कौशल, पूंजी और संसाधनों की कमी है।

जीवनशैली के संदर्भ में यह पाया गया है कि श्रमिकों के उपभोग पैटर्न, आवासीय स्थिति और सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आया है, लेकिन यह परिवर्तन मुख्यतः आर्थिक दबाव और रोजगार अस्थिरता से प्रभावित है। कई श्रमिकों को जीविका के लिए प्रवास करना पड़ रहा है, जिससे उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि कृषि यंत्रीकरण ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसके लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचे हैं। अनुसूचित जाति श्रमिक इस परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित वर्गों में से एक हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नीति-निर्माण में इस वर्ग की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें कौशल विकास, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि ग्रामीण विकास समावेशी और न्यायसंगत बन सके।

संदर्भ सूची

- Agarwal, B. (1983). *Mechanization in Indian agriculture: Implications for labor use and gender roles*. International Labour Organization.
- Breman, J. (1996). *Footloose labour: Working in India's informal economy*. Cambridge University Press.
- Desai, A. R. (1979). *Rural sociology in India*. Popular Prakashan.
- Dreze, J., & Sen, A. (2013). *An uncertain glory: India and its contradictions*. Princeton University Press.
- Jodhka, S. S. (2012). *Caste*. Oxford University Press.
- Mukherjee, R. (1957). *The dynamics of rural society*. Orient Longman.
- Rao, M. S. A. (1979). *Social movements in India*. Manohar Publishers.
- Srinivas, M. N. (1966). *Social change in modern India*. University of California Press.

Weber, M. (1978). Economy and society. University of California Press.

शर्मा, आर. (2005). ग्रामीण समाजशास्त्र. रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

सिंह, के. (2010). भारतीय ग्रामीण समाज और परिवर्तन. प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।

यादव, आर. (2012). भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन. मोतीलाल बनारसीदास।

मिश्रा, एस. (2008). कृषि एवं ग्रामीण विकास. साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

शुक्ल, पी. (2015). ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना. ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।

दुबे, एस. सी. (2001). भारतीय ग्रामीण समाज. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।

Indian Reports and Government Sources

Government of India. (2011). Census of India 2011: Uttar Pradesh district handbook. Office of the Registrar General.

National Sample Survey Office. (2014). Employment and unemployment situation in India. Ministry of Statistics and Programme Implementation.

World Bank. (2007). Agriculture for development. World Bank.

Official Websites (Ambedkar Nagar & Government Sources)

District Ambedkar Nagar Official Website. (n.d.). Government of Uttar Pradesh. <https://ambedkarnagar.nic.in>

Government of Uttar Pradesh. (n.d.). Agriculture and rural development reports. <https://up.gov.in>

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (n.d.). Government of India. <https://agricoop.gov.in>

Census of India. (n.d.). Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. <https://censusindia.gov.in>

National Informatics Centre (NIC). (n.d.). District information system for Ambedkar Nagar. <https://nic.in>

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.